आवंटितियों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अधीन गुजरात को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) से (ग) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आंशिक राशि भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा कुछ खपत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, वितरित भूमि के प्रति हैक्टेयर 2500 रुपये के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है । योजना 1975–76 से क्रियान्वित की जा रही है । 1992–93 तक इस योजना के के अन्तर्गत गुजरात को केन्द्रीय सहायता के रूप में 177.22 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है ।

**Introduction of DPAP Scheme in Mundra Taluka**

2109. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Mundra Talukas of Kachh District of Gujarat State Assembly constituency seat is not notified under DPAP scheme of the Central Government.

(b) whether it is also a fact that the Mundra Constituency of Kachh District of Gujarat State is notified as S.C. (Scheduled Caste) seat;

(c) whether DPAP scheme has been introduced in Mundra Taluka;

(d) if so, when it has been introduced and if not, the reasons therefor;

(e) whether any proposal has been submitted by the Gujarat Government to cover Mundra Taluka under DPAP scheme; and

(f) if so what steps have been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) The Mundra Assembly Constituency of Kutch District is notified as a reserved constituency for the Scheduled Castes.

(c) and (d) No, Sir. At present the DPAP is implemented in the areas identified on the basis of rainfall and irrigation criteria fixed by the Task Force 1982 headed by Dr. Swaminathan and as modified by the Inter Departmental Group in 1984. As per the Criteria seven talukas of Kutch namely, Abdasa, Anjar, Bhachav, Bhuj, Lakhapat, Nakhatrana and Rapar were identified and are presently covered under DPAP. The Mundra Taluka was not included as it did not fulfil the criteria.

(e) Yes, Sir.

(f) The State Government have been informed that the DPAP will continue to be implemented in the already identified areas until a Sparate Committee further examines the aspects of inclusion and exclusion of areas.

**उत्तर प्रदेश में फालतू भूमि को राज्य के ग्रामीण निर्धनों में बांटे जाने संबंधी निदेश**

2110. **श्री ईशदत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फालतू भूमि को ग्रामीण निर्धनों में बांटे जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निदेश दिये हैं :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन निदेशों का उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सीमा तक पालन किया है ; और

(घ) संयुक्त पट्टे और महिलाओं को भूमि स्वामित्व सुलभ कराने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) और (ख') मार्च 1922 में हुये राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में विवादों से मुक्त फालतू भूमि के वितरण की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 1992 कर दिया गया था । यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्यों में राजस्व न्यायालयों के समक्ष मुकद्दमेंबाजी में फंसी अधिकतम सीमा से फालतू भूमि में से 75% को मामलों से निपटाकर रिलीज कराया जाना चाहिये और इस प्रकार रिलीज कराई गई भूमि का वितरण किया जाना चाहिये । तदनुसार, राज्य सरकारों को कदम उठाने की सलाह दी गई है ।

(ग) उपरोक्त सिफारिशों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991–92 और 1992–93 में निम्नलिखित क्षेत्र का वितरण किया है :–

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि (क्षेत्र एकड़ में) |
|---|---|---|
| 1991–92 | 1250 | 2294 |
| 1992–93 | 1250 | 3188 (जनवरी 93) |

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अधिनियम में कमजोर वर्गों के सदस्यों को पट्टा देने के प्रावधान हैं लेकिन पुरुषों और महिलाओं में कोई भेद नहीं रखा गया है । तथापि, वे पति और पत्नी के संयुक्त नामों में पट्टा जारी करने की सिफारिश की जांच कर रहे हैं ।

**Innovation of Bullock Cart**

2111. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether efforts are being made to innovate the functioning of Bullock Cart; if so, the details thereof.

(b) wheher any R and D is in progress;

(c) what is the cost of production of a bullock cart; and

(d) what is the value of the services that each cart carries per year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) The Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART), which is an autonomous body under the aegis of this Ministry is responsible for transfer of appropriate technology to various agencies to encourage adoption of modern techniques and appropriate technology in rural development. The Council have supported the organisation named Centre for Action Research and Technology, Bangalore for development of the following different designs of Bullock Cart:—

—Bangalore Type—Double Animal CART

—Bangalore Type—Single Animal CART

—Madras Garbage Removal—Double Animal CART.

—Villupuram Type with Spring Loaded Yoke—Double Animal CART

—Palcode Type—Double Animal CART.

(c) Each of these designs costs Rs. 9,000 to 10,000 on an average.

(d) The bullock carts in rural areas are not used for commercial haulage of goods on service fees basis. Carts are only used for transportation of personal agricultural produce/related material. By and large the carts are used for an average 100 days in a year.